पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International 1983-2023

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 24 , अंक 2/2023

अर्थव्यवस्था: भारतीय उद्योग जगत विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है, उस पर भरोसा रखें

भारत को अपनी व्यापार नीति में किसी भी संरक्षणवाद को बढ़ावा देने से बचने पर ध्यान देना होगा। पिछले कुछ वर्षों में व्यापार और आर्थिक नीति में सुधारों को उन उपायों के साथ मिलाने की प्रवृत्ति रही है, जो प्रभावी रूप से आयात को कम करने और घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के उद्देश्य से हैं।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि, 'मेरा मानना है कि विदेशों से आयातित माल की बजाय भारत में निर्मित सामान को अपनाने की जरूरत है, चाहे वह दूसरे दर्जे का ही क्यों न हों।' तब से लेकर अब तक कई दशक बीत चुके और आर्थिक उदारीकरण को भी 30 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। अब समय आ गया है कि संरक्षणवाद को बढ़ावा देने वाली नीतिगत सोच का पूरी तरह से परित्याग कर दिया जाए।

संरक्षणवादी सोच को चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में तब सुर्खियां बटोरी, जब दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाषण देते हुए उन्होंने दुनिया को संरक्षणवाद के युग में वापस ले जाने वालों को फटकार लगाई थी। आज यह पूछने की आवश्यकता है कि क्या हमारी नीतिगत कथनी एवं करनी एक समान है? तुलनात्मक रूप से देखें तो हम पाते हैं कि भारत प्रतिद्वंदी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं

विशेष रूप से दक्षिणपूर्व एशिया की तुलना में उच्च आयात शुल्क स्तर बनाए रखता है। यद्यपि भारत ने हाल ही में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने में नए सिरे से रुचि दिखाई है। गौरतलब है कि भारत कई महत्वपूर्ण मेगा-क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं का सदस्य नहीं है।

हमें इस मानसिकता से खुद को मुक्त करने की आवश्यकता है कि भारतीय उद्योग विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। व्यापार घाटे को आवश्यक तौर पर हानिकारक समझना एवं व्यापार उदारीकरण का हमारी अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों में नौकरियों के लिए अहितकर समझना कच्चा अर्थशास्त्र माना जाएगा। हमने पिछले 25 वर्ष में देखा है कि मौका मिले तो भारतीय उद्यमी कमाल कर सकते हैं।

सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में भारत के व्यापार पर उच्च-स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी) की 2019 की रिपोर्ट में कहा गया था कि निर्यात और आयात दोनों ही स्पर्धा क्षमता को मजबूती देते हैं। हाल ही में भारत के डेयरी क्षेत्र को लेकर नीति आयोग के कृषि विशेषज्ञ रमेश चंद ने चेतावनी दी है कि अगर कोई देश समुचित आयात करने का अनिच्छुक हो या असमर्थ हो, तो वह दमदार निर्यात नहीं कर सकता है। इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

समय की आवश्यकता है कि टैरिफ निर्धारण के लिए एक समर्पित स्वतंत्र टास्क फोर्स गठित की जाए एवं उसी के माध्यम से टैरिफ की आवधिक समीक्षा को संस्थागत बनाया जाए। ऐसा करके हम आयात एवं निर्यात में संतुलन एवं आर्थिक सशक्तीकरण की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय से भारत की टैरिफ नीति को अधिक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाने में भी मदद मिलेगी। ये व्यापार नीति पर उन शिफारिशों की एक श्रृंखला का भी हिस्सा थे, जो 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में सरकार के वाणिज्य विभाग को प्रदान किए गए हैं। टैरिफ की समय-समय पर समीक्षा कर हम वर्तमान में चल रहे मुक्त व्यापार समझौतों में भारतीय हितों की सुरक्षा कर सकते हैं।

बातचीत के जरिए उन टैरिफ रियायतों को प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो भारतीय उत्पादकों द्वारा आयातित इनपुट की सस्ती सोर्सिंग को सक्षम बना सकें और घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें। प्रतिस्पर्धा की यह क्षमता व्यापार उपचारात्मक उपायों जैसे एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग शुल्कों के अंधाधुंध आरोपण के माध्यम से हासिल नहीं की जा सकती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एचएलएजी रिपोर्ट और उपरोक्त रणनीतियों को अपनाने की महती आवश्यकता है। आसान भाषा में कहा जाए, तो आर्थिक समृद्धि लाने के लिए स्पर्धा बढ़ानी होगी और संरक्षणवाद का मोह छोड़ना होगा। यह जितना जल्दी समझ आ जाए, उतना अच्छा है।

प्रदीप एस महता
महामंत्री, 'कट्स' इन्टरनेशनल

इस अंक में...

- इंजीनियर्स की 'दिव्य दृष्टि' 3
- चिरंजीवी में 25 लाख का बीमा? 4
- भ्रष्ट कितना भी ताकतवर हो, बख्शा न जाए .. 6
- फ्री बिजली से बिगड़ा डिस्कॉम का गणित 8
- मिशन डिजिटल महिला का शुभारंभ 10

जी-20 के तहत आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन

जन जुड़ाव से हो रहा है लोकतंत्र सशक्त-रामचरण बोहरा

''भारत के इस अमृतकाल में जी-20 की अध्यक्षता को भारत सरकार द्वारा एक अवसर में बदलने की मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य एवं धरातल स्तरीय वैचारिक मंथन से जन-उपयोगी सुझाव सामने आ रहे हैं और जन भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। इन प्रक्रियाओं से भारत के लोकतंत्र को मजबूती मिल रही है।''

उक्त विचार जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा ने 'कट्स इंटरनेशनल द्वारा 'ग्राम' मैसूर के सहयोग से जी-20 व सी-20 के अंतर्गत डिलीवरिंग डेमोक्रेसी कार्य समूह के तहत आयोजित क्षेत्रीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने जी-20 के तहत अपने संसदीय क्षेत्र में की जा रही गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में कमलचन्द योगी, वरिष्ठ प्राचार्य, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर ने लोकतंत्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं मानव विकास के पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने वर्तमान में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान के बारे में भी अपने विचार रखे।

सम्मेलन में 'ग्राम' मैसूर के संयोजक राजीवदास गुप्ता ने जी-20 के तहत आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों तथा जी-20 के देशों के नवीनतम नवाचारों को प्रचारित व प्रसारित करने के प्रयासों की जानकारी दी। 'कट्स' के निदेशक अमृत सिंह द्वारा जी-20 के तहत किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया गया तथा कार्यक्रम के संयोजक मधुसूदन शर्मा ने सी-20 के तहत संपूर्ण भारत में आयोजित की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में आए सुझावों को जी-20 सचिवालय तक पहुंचाया जाएगा।

कार्यक्रम में अभिजीत कुमार, महापौर, भरतपुर एवं मनीष पारीक, पूर्व उपमहापौर, जयपुर ने लोकतंत्र को सशक्त, पारदर्शी, सहभागी व उत्तरदायी बनाने जैसे विषयों पर सारगर्भित चर्चा कर अपने कई महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। वहीं, श्रीमती शबनम अजीज, एजुकेट गर्ल्स तथा विभिन्न राज्यों के सरपंचों, जनप्रतिनिधियों ने सहभागियों के साथ सार्थक चर्चा कर विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव दिए। कार्यक्रम में उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए 40 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

शहरी निकायों के अधिकारियों का क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित

'कट्स' द्वारा शहरी निकायों की क्षमतावर्धन कार्यक्रम राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग तथा ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग, नई दिल्ली के सहयोग से जयपुर में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में 'कट्स' के अमरदीप सिंह, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि पिछले एक दशक से शहरी सुशासन और शहरी निकायों के क्षमतावर्धन के लिए 'कट्स' कार्य कर रहा है। 'कट्स' स्वायत्त शासन विभाग के साथ एक सहमति-पत्र के अंतर्गत शहरी निकायों के क्षमतावर्धन हेतु विगत वर्षों से कार्य कर रहा है। इस गैर वित्तीय सहमति-पत्र के अनुसार जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की क्षमतावर्धन हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी निकायों के ज्ञानवर्धन के द्वारा आम नागरिकों की जीवन शैली में सुधार करना है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक अमृत सिंह ने परियोजना के उद्देश्य एवं कार्यशाला के विभिन्न उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। डॉ. कमलदीप शर्मा, स्टेट नॉडल ऑफीसर ने अपने उद्बोधन के दौरान सभी अधिकारियों को मुंसिपल फाइनेंस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता जताई।

कार्यक्रम में डॉ. हिमानी तिवारी ने देश में चल रहे अच्छे प्रयासों को समझ कर उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि देश में हैदराबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। राजस्थान से अधिकारियों ने वहां की कार्यप्रणाली देखी है। जिसे हम राजस्थान में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं एवं काफी हद तक सफल भी रहे हैं। परंतु हमारे यहां किए गए कार्यों का सही ढंग से दस्तावेजीकरण नहीं हो पा रहा है। जिससे हम राष्ट्रीय रैंकिंग में पीछे रह रहे हैं।

कार्यक्रम में हैदराबाद के डॉ. डी. सुधाकर ने विभिन्न मुद्दों पर सभी प्रतिभागियों का क्षमतावर्धन किया। उन्होंने कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि शहरी निकायों में सुधार के लिए हमें आम नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में जयपुर नगर निगम हेरिटेज एवं ग्रेटर से लगभग 35 अधिकारियों ने भाग लिया।

राजीव गांधी स्कॉलरशिप में झमेला

प्रदेश में राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना का उद्देश्य राजस्थान के उन छात्रों को आर्थिक सहायता स्कॉलरशिप के रूप में प्रदान करना है, जो पैसों के अभाव में गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं जा सकते। मतलब उन गरीब होनहार बच्चों के लिए यह योजना लाई गई, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक हो।

लेकिन अब 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाई वाले बड़े उच्चवर्ग के अधिकारियों के लिए इस योजना को लागू कर देना बड़े सवाल पैदा करता है। क्यों इस योजना में सरकार ने इनकम स्लैब में छूट दी, जिससे 62 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले आईएएस दंपत्ति के बच्चे अब स्कॉलरशिप योजना का लाभ उठाकर विदेश में पढ़ रहे हैं? यह ही नहीं 3 करोड़ वार्षिक कमाने वाले कारोबारी के बच्चे भी सरकारी योजना से जुड़ गए हैं? अब यह दलील दी जा रही है कि योजना में आवेदन कम आए तो अधिक आय वालों के प्रावधान जोड़े गए हैं।

(दै.भा., 26.04.23, 27.04.23)

सौभाग्य योजना में सामने आया फर्जीवाड़ा

प्रदेश के बांसवाड़ा जिले में केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना में 1.25 करोड़ रुपए के बिलों के भुगतान में फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामला बागीदौरा-आनंदपुरी योजना के तहत गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन से जुड़ा है। जिसमें ठेकेदार ने कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी आधार नंबर दर्ज कर और फर्जी कनेक्शन दिखाते हुए भुगतान उठा लिया।

डिस्कॉम के अधिकारियों ने भी बिलों का भौतिक सत्यापन और अन्य जांचें किए बिना ही भुगतान कर दिया। गौरतलब है, कनेक्शन के लिए डिस्कॉम द्वारा केवल 649 मीटर दिए गए, लेकिन फर्म को भुगतान 1220 कनेक्शन का कर दिया। यानी जब मीटर ही नहीं मिले तो कनेक्शन कैसे हो गए? मामले की उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है। *(दै.भा., 02.04.23)*

कर्मचारियों ने लगाई खातों में सेंध

जीपीएफ खाते से संबंधित लेजर में छेड़छाड़ कर कर्मचारियों द्वारा करीब 6 करोड़ रुपए निकालने का मामला सामने आया है। आईटी सिस्टम में हेरफेर होते ही 24 घंटे के भीतर ही मामला खुल गया और वित्त विभाग तत्काल हरकत में आ गया। राज्य सरकार ने बीमा प्रावधायी निधि के 3 कर्मचारियों को निलम्बित किया है।

बताया जा रहा है कि खाते से छेड़-छाड़ करने वाले तीनों कर्मचारी क्लर्क व सुपरवाइजर स्तर के हैं। साथ ही जिन 12 कर्मचारियों के खातों से राशि निकाली गई है उनकी भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है। यह पूरा मामला आईटी सिस्टम की वजह से खुला है। तीन करोड़ रुपए की निकासी रुकवा दी गई है, वहीं 78 लाख रुपए सरकार ने वसूल भी कर लिए हैं। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं और राशि का तो लेन-देन नहीं हुआ है और कोई अन्य कर्मचारी तो इस मामले में लिप्त नहीं है। *(रा.प., 03.06.23)*

पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान फिसड्डी

पर्यावरण संरक्षण के मामले में राजस्थान सबसे फिसड्डी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फीगर्स 2023 में इस स्थिति का खुलासा किया गया है। सीएसई ने पर्यावरण के विभिन्न मानकों के अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित मानकों में सबसे कम स्कोर करने वाला राज्य राजस्थान है। जिसे महज 27 अंक मिले हैं। राजस्थान 30 प्रतिशत से कम स्कोर करने वाला एक मात्र राज्य है। तेलंगाना का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। इसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र का रहा है। भूजल दोहन में राजस्थान की स्थिति बहुत ही खराब है। भूजल दोहन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। यहां 219 अति दोहन वाले क्षेत्र हैं।

(रा.प., 05.06.23)

महिलाओं से जुड़ी योजनाओं में धांधली

उदयपुर सहित 21 जिलों में महिला और बाल विकास विभाग में 63.57 लाख रुपए की धांधली सामने आई है। मामला साल 2020-21 के दौरान महिलाओं से जुड़ी योजनाएं चलाने के लिए ली गई अग्रिम राशि का है जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं।

निदेशक रामावतार मीणा 15 महीने में दो बार पत्र लिख चुके हैं, फिर भी न तो हिसाब दिया जा रहा है, न ही राशि लौटाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में यह राशि सर्वाधिक 17.53 लाख रुपए है। उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलना वित्तीय अनियमितता माना जाता है। उदयपुर में यह आंकड़ा 1.20 लाख रुपए है। जिलों के अधिकारी न तो निदेशक की सुन रहे है और न ही वित्त विभाग की। अब इस रकम की रिकवरी की तैयारी है। *(दै.भा., 10.06.23)*

इंजीनियर्स की 'दिव्य दृष्टि'...

प्रदेश में जलदाय विभाग के इंजीनियर सरकार की मंशा के विपरीत कार्यालय में बैठकर ही अपनी 'दिव्य दृष्टि' से अपने जिले की पेयजल आपूर्ति समस्याएं और परियोजनाओं की जमीनी हकीकत देख रहे हैं। इंजीनियरों की यह कार्यशैली 6 जून को अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सामने आई।

जमीनी हकीकत से रहे दूर

- *ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी में पानी को लेकर हाहाकार मचा है*
- *जेजेएम की परियोजना धीमी चल रही है।*
- *पानी के सैंपल ही नहीं लिए जा रहे*
- *परियोजनाओं की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे*
- *जयपुर शहर में भी पेयजल प्रोजेक्ट की गति धीमी*

समीक्षा बैठक में पता चला कि बीते पांच महीने में 187 इंजीनियर्स ने एक भी दौरा नहीं किया, जिनमें मुख्य अभियंता, अति. मुख्य अभियंता और मुख्य रसायन स्तर के बड़े बड़े अफसर भी शामिल हैं। समीक्षा बैठक में कार्यशैली की पोल खुली तो इंजीनियरों ने डबल चार्ज का बहाना बना दिया।

(रा.प., 16.06.23)

चिरंजीवी में 25 लाख का बीमा?

भले ही चिरंजीवी में बीमा 25 लाख रुपए सालाना का हो, लेकिन इलाज के लिए रोजाना 6 हजार रुपए तक खर्च का पैकेज गंभीर रोगियों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया है। इसमें दवाइयां व जांच आदि सब खर्च सम्मिलित है। इससे गंभीर मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में नहीं हो पा रहा।

सच यह है, गंभीर बीमार मरीज की जान बचाने के लिए पहले ही दिन 15 से 20 हजार का खर्चा होना एक सामान्य बात है। ऐसे में निजी अस्पताल 6 हजार रुपए के बाद इलाज करना ही बंद कर देते हैं। परिजन भी चिरंजीवी में होने के कारण ज्यादा पैसा देना नहीं चाहते। ऐसे में निजी अस्पताल परिजनों को सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराने की सलाह देते हैं। क्योंकि निजी अस्पतालों के चिकित्सकों के अनुसार पैकेज में जटिलता के इलाज की अलग से व्यवस्था ही नहीं की गई है। *(रा.प., 07.05.23)*

बढ़ती जा रही है बेरोजगारी की समस्या

देश में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अप्रेल महीने में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.83 फीसदी पर पहुंच गई इससे पहले मार्च में ये 7.60 फीसदी पर थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी के मुताबिक मार्च 2022 में शहरी बेरोजगारी की दर 9.22 फीसदी और ग्रामीण बेरोजगारी की दर 7.18 फीसदी रही। बेरोजगारी गांवों से ज्यादा शहरों में बढ़ी।

रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा और राजस्थान में दर्ज की गई है। हरियाणा में यह 34.5 फीसदी और राजस्थान में 28.8 फीसदी है। जबकि हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम में सबसे कम बेरोजगारी देखी गई। *(रा.प., 03.05.23)*

जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ियां

प्रदेश में जल जीवन मिशन के साथ ही शहरी व ग्रामीण पेयजल स्कीम में कई गड़बड़ियां होने और ठेकेदारों से मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा करने के मामले सामने आए हैं। ठेकेदार विभाग के इंजीनियरों से मिलीभगत कर फील्ड में डक्टाइल आइरन के बजाए एचडीपीई की पाइप लाइन डाल कर करोड़ों का फर्जी भुगतान उठा रहे हैं।

विभाग की विजिलेंस विंग व क्वालिटी कंट्रोल विंग की लापरवाही का फायदा उठाकर पाइपलाइन डालने व टंकिया बनाने में भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। एक साल में 45 इंजीनियरों को सस्पेंड व एपीओ किया है और 60 इंजीनियरों के खिलाफ शिकायतों की जांच भी चल रही है। *(दै.भा., 21.05.23)*

मनरेगा में नहीं मिला पूरा रोजगार

मनरेगा में सरकार ने गारंटी तो 100 दिन की दी है, लेकिन ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में औसतन 43 दिन ही रोजगार मिल रहा है। 54 लाख से ज्यादा परिवारों में से 100 दिन रोजगार सिर्फ 1.42 लाख परिवारों को ही मिला। 53 लाख परिवारों को 57 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा।

पंचायतीराज विभाग की चार साल की दिसंबर तक की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में 100 दिन पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने की घोषणा की है। मनरेगा में 2021-22 में खर्च 10462 करोड़ रुपए था, इस साल यह 6878 करोड़ रुपए रहा। यानी पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत तक कम है। *(दै.भा., 14.05.23)*

निजी स्कूलों को दी गई डबल किस्त

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जयपुर जिले में निजी स्कूलों को दी जाने वाली पुनर्भरण राशि के भुगतान के मामले में गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिले में करीब 250 निजी स्कूलों को 6 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया जबकि उनके खाते में 3 करोड़ रुपए का ही भुगतान होना था।

अब शिक्षा विभाग के अधिकारी अधिक भुगतान किए गए 3 करोड़ रुपए की वसूली में लगी है। अधिकारी फोन कर पैसा वापस मांग रहे है। इस मामले में किसकी लापरवाही रही यह तय नहीं हो पाया। यह राशि दो माह से भी अधिक समय से स्कूलों के खाते में पड़ी है। इनमें से कुछ निजी स्कूलों ने चैक से राशि वापस कर दी, लेकिन कई स्कूलों ने खाते से पैसा निकाल कर काम में ले लिया। अब खातों में पैसा नहीं होने से वे जमा नहीं करा पा रहे। *(दै.भा., 06.06.23)*

डीलर ने बेचा गरीबों के हक का गेहूं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में गरीबों को मिलने वाले 17733 किलोग्राम गेहूं को जगतपुरा के एक राशन डीलर ने 3.54 लाख रुपए में बेच दिया। डीएसओ महेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि उचित मूल्य दुकान संख्या 558 एफपीएस कोड 7211 जगतपुरा रामनिवास मीणा की गेहूं नहीं देने की शिकायत मिली।

इस पर इंस्पेक्टर अशोक कुमार योगी को जांच के लिए कहा गया। जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। भारत सरकार किसानों से यह गेहूं 22 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीद कर गरीबों को 2 रुपए किलो में देती है। डीलर को इस गेहूं को गरीबों को बांटना था। गेहूं के गबन की रिपोर्ट एयरपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई है। थानाधिकारी का कहना है कि मामले की जांच जारी है। *(दै.भा., 22.04.23)*

अनुप्रति कोचिंग योजना में फर्जीवाड़ा

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 90 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। बांसवाड़ा जिले में संचालित एक कोचिंग संस्था के संचालकों ने बिना कोचिंग दिए 342 विद्यार्थियों के नाम से 90 लाख रुपए का अनुदान उठा लिया।

दरअसल, लाखों रुपए का अनुदान लेने के लिए कोचिंग सेंटर ने 342 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना बताया। जिस पर सेंटर को 1.57 करोड़ रुपए का अनुदान मिलना था। सेंटर में फर्जीवाडा इतना था कि जितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना बताया, उतनी तो उनके बैठने की व्यवस्था तक नहीं थी। इतना ही नहीं सेंटर के पास विद्यार्थियों का कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। योजना की गाइडलाइन के मुताबिक विद्यार्थियों के बायोमैट्रिक्स से हाजिरी लेनी थी, लेकिन इसके लिए डिवाइस तक नहीं लगाया। *(दै.भा., 04.06.23)*

अमीर देश नहीं निभा रहे गरीब देशों से किया 'जलवायु वित्त' का वादा

ग्रीनहाउस उत्सर्जन में वृद्धि जारी है और जलवायु परिवर्तन कहर बरपा रहा है। वही, अमीर देशों ने निम्न व मध्यम आय वाले देशों को क्लाइमेट-चेंज से निपटने व स्वच्छ अर्थव्यवस्था के लिए जलवायु वित्त के रूप में प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर देने का वादा नहीं निभाया।

ऑक्सफैम की क्लाइमेट फाइनेंस शैडो रिपोर्ट, 2023 के अनुसार 2020 में गरीब देशों को दिए गए जलवायु वित्त का वास्तविक मूल्य 21 अरब डॉलर से 24.5 अरब डॉलर के बीच था। वहीं, विकसित राष्ट्रों की ओर से 83.3 अरब डॉलर वितरित किए गए। जलवायु परिवर्तन के कारण नुकसान और क्षति अभी भी क्लाइमेट फाइनेंस का अधिकारिक हिस्सा नहीं है। ऑक्सफैम ने चिंता जताई है कि जलवायु अनुकूलन फंडिंग पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। जबकि तीन साल में भारत, पाकिस्तान और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका ने रेकॉर्ड हीटवेव का सामना किया। इधर,अल्प विकसित देशों पर ऋण संकट बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर के लक्ष्य से भी आगे बढ़ने का समय है। *(रा.प., 13.06.23)*

सेहत को प्रभावित करता है प्लास्टिक

बीपीए यानी बिस्फेनॉल एक औद्योगिक रसायन है, जिसका उपयोग 1950 के दशक से कुछ प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। हम जिन प्लास्टिक के डिब्बों में खाने-पीने का सामान रखते हैं और जिन प्लास्टिक की बोतलों को पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें अक्सर पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक का उपयोग होता है।

इन कंटेनरों और बोतलों में से बीपीए हमारे भोजन या पेय पदार्थों में रिस सकता है और इससे हमारी सेहत पर भी असर होता है। खासतौर पर शिशुओं और बच्चों के मस्तिष्क और प्रोस्टेट ग्रंथी पर इसका ज्यादा असर होता है। इसका असर बच्चों के व्यवहार पर भी पड़ सकता है। इस बारे में किए गए रिसर्च बताते हैं कि इससे ब्लडप्रेशर, टाइप 2 डाइबिटीज, हृदयरोग और कैंसर तक हो सकता है। *(दै.भा., 25.05.23)*

हमारे इनोवेशन की विदेशों में धाक

विदेशों में हमारे स्टार्टअप्स अब अलग पहचान बनाने लगे हैं। नई स्टार्टअप पॉलिसी में प्रावधान है कि युवाओं के आइडिया पर राज्य सरकार भी निवेश करेगी। सरकार को स्टार्टअप बिजनेस आइडिया पसंद आया तो बतौर इक्विटी 5 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा। यानी, बिजनेस में लाभ और हानि में सरकार की भी हिस्सेदारी होगी।

राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से प्रदेश के लिए नजीर बने स्टार्टअप्स और उनसे जुड़े लोगों की जानकारी मांगी है। इनोवेशन को बिजनेस के रूप में डवलप करने वाले युवा ऑस्ट्रिया, जर्मनी और यूएस जाएंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के विद्यार्थियों से भी स्टार्टअप्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए उन स्टार्टअप्स को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्होंने लीक से हटकर काम किया है। प्रदेश में यूनिसेफ के साथ मिलकर स्कूलों में स्टार्टअप आइडिया पर काम चल रहे हैं। *(रा.प., 27.04.23)*

प्लास्टिक बना बड़ी मुसीबत...

प्लास्टिक का बढ़ता प्रदूषण पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहा है। इसे कम करने के लिए रिसाइक्लिंग का सहारा लिया जाता है। लेकिन स्कॉटलैंड में स्ट्रेथक्लाइड यूनिवर्सिटी और कनाडा में डलहौजी यूनिवर्सिटी में पर्यावरण इंजीनियरों ने पाया कि प्लास्टिक रिसाइक्लिंग तकनीकें अनजाने में पर्यावरणीय माइक्रोप्लास्टिक बढ़ा रही हैं।

रिसाइक्लिंग के दौरान प्लास्टिक की वस्तुओं को कई बार धोया जाता है। इस दौरान जल निकायों में प्रति वर्ष कई टन माइक्रोप्लास्टिक पहुंचने की आशंका है। प्लास्टिक, द पोटेंशियल एंड पॉसिब्लिटीज रिपोर्ट के अनुसार भारत एक वर्ष में 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। लेकिन सिर्फ 30 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल किया जाता है। *(रा.प., 15.05.23)*

धरती के गर्म होने का पड़ेगा प्रभाव

पर्यावरण विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी दे रहे हैं कि धरती के गर्म होने से मानव स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ेगा। नए अनुमान के मुताबिक 2030 तक ग्लोबल तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। नेचर साइंटिफिक रिपोर्टस में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के गर्म होते पानी से इंफेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया बढ़ेंगे। विब्रिओ वलनिफिकस बैक्टीरिया खारे पानी में पनपता है।

ब्रिटेन की ईस्ट एंग्लिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पाया है कि विब्रिओ वलनिफिकस मैक्सिको की खाड़ी के समुद्र तट से अमेरिका के उत्तरी राज्यों की ओर बढ़ रहा है। रिसर्चर एलिजाबेथ आर्चर कहती हैं, हम ऐसे इलाकों में इंफेक्शन देख रहे हैं जहां इस बैक्टीरिया के मामले बहुत कम थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2081 तक अमेरिका के पूर्वी तट पर हर राज्य तक विब्रिओ का इन्फेक्शन फैल सकता है। *(दै.भा., 09.04.23)*

प्रदीप महता एनजीओ सलाहकार समिति में नियुक्त

विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक डॉ. न्गोजी ओकोन्जो-इवेला ने 'कट्स' इंटरनेशनल के महामंत्री प्रदीप एस. महता को 12 सदस्यीय एनजीओ सलाहकार समिति में नियुक्त किया है।

महता तीसरी बार विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशकों द्वारा सम्मानित हुए हैं और वे एकमात्र भारतीय हैं, जिन्हें यह सम्मान मिला है। इससे पहले उन्हें 2003-05 एवं 2012-13 में भी सलाहकार समितियों में नियुक्त किया गया था।

भ्रष्ट कितना भी ताकतवर हो, बख्शा न जाए

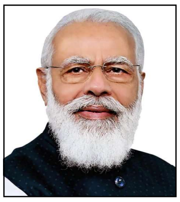

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए आज राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। अधिकारियों को बिना हिचकिचाहट के भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, भले ही वे कितने भी ताकतवर हों। उन्होंने भ्रष्टाचार को लोकतंत्र और न्याय की राह में सबसे बड़ा रोड़ा करार देते हुए कहा कि सीबीआई की प्रमुख जिम्मेदारी भारत को इससे मुक्त कराना है।

सीबीआई के हीरक जयंती समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, जिन लोगों को दशकों तक भ्रष्टाचार से लाभ हुआ, उन्होंने एक परिस्थितिकी तंत्र बनाया है जो जांच एजेंसियों पर हमला करता है। लेकिन एजेंसियों को भ्रष्टों की शक्ति और उन्हें कलंकित करने के लिए उनके बारे में फैलाई गई कहानियों से विचलित नहीं होना चाहिए। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा। हमारे प्रयासों में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। यह देश की और लोगों की इच्छा है। देश, कानून और संविधान आपके साथ है। सीबीआई के हीरक जयंती समारोह पर उन्होंने एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। *(दै.भा., 04.04.23)*

शासन के प्रति उठ रहा विश्वास

जोधपुर हाइकोर्ट न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की एकल पीठ ने एक भ्रष्टाचारी कर्मचारी मदनलाल की याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा याचिकाकर्ता बहुत गंभीर कदाचार के लिए अनुशासनात्मक जांच का सामना कर रहा है। उसे गिरफ्तार किया जा चुका है और निलंबित भी कर दिया गया था।

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार न केवल संवैधानिक शासन की अवधारणा के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की नींव व कानून के शासन के लिए भी खतरा है। यह बहुत पीड़ादायक है कि सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार, शासन में आम आदमी के विश्वास को कम कर रहा है। भ्रष्टाचार राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों को बाधित करता है। जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। याचिकाकर्ता भ्रष्टाचार में गंभीर रूप से शामिल पाया गया था, इसलिए इस स्तर पर कोई भी राहत नहीं दी जा सकती। *(रा.प., 11.05.23)*

अभियोजन स्वीकृति में होती है देरी

हमारी सरकारें भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेन्स की बात तो खूब करती है पर धरातल पर मामलों की अनदेखी करना ही सबका ध्येय बनता जा रहा है। बड़ी मछलियों को बचाने के चक्कर में अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों को अटकाने के कई मामले सामने आते हैं।

आंकड़ों पर नजर डाले तो राजस्थान में नौकरशाही के भ्रष्टाचार से जुड़े 618 मामलों में आज भी अभियोजन स्वीकृति का इंतजार है। इनमें सरकार के स्तर पर 59 और विभाग के स्तर पर 559 मामले लंबित है। समय-समय पर विधानसभा में भी ऐसे मामले उठते रहे हैं, पर सरकार सिवाय स्पष्टीकरण के कुछ नहीं करती। सरकार पर आरोप तो यह भी लगता है कि 'बड़ी मछलियों' को बचाने के चक्कर में अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों को अटका कर रखा जाता है। ऐसे में फरियादियों को बरसों तक न्याय नहीं मिलता। अभियोजन स्वीकृति के बिना कोर्ट में भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती।

(रा.प., 23.06.23)

आलमारी से निकला खजाना

केंद्र सरकार की ओर से दो हजार रुपए के नोट पर रोक लगाने के कुछ देर बाद ही जयपुर में सचिवालय से करीब 25 कदम दूरी पर सूचना प्रौद्योगिकी भवन के बेसमेंट में रखी सरकारी आलमारी से एक बैग में 2.31 करोड़ रुपए नकद और एक किलो सोना निकला। इससे पूरी सरकार में खलबली मच गई। आखिर मामले पर से पर्दा उठा आलमारी के ऊपर लगे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से।

यह खजाना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के ही संयुक्त निदेशक व स्टोर इंचार्ज वेद प्रकाश यादव ने रखा था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि यह रुपए उसके हैं और उसने यह पैसे रिश्वत से इकट्ठे किए थे। पुलिस कमिश्नर आनन्द श्रीवास्तव ने बताया कि सोने की सिल्ली भी उसने ही खरीदी थी। मामला रिश्वत से जुड़ा होने के कारण अब एक रिपोर्ट के साथ पुलिस ने आरोपी अधिकारी वेद प्रकाश को एसीबी को सौंप दिया। अब एसीबी जांच करेगी कि यादव ने रिश्वत किन-किन लोगों से किस काम के बदले ली है। *(रा.प., 21.05.23)*

भ्रष्टाचार में डूबा राजस्व विभाग

जनता के कामों में गड़बड़ी व मिलीभगत को लेकर प्रदेश में तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के खिलाफ राजस्व विभाग, रेवन्यू बोर्ड व जिला प्रशासनों को पिछले एक साल में 1450 शिकायतें मिली हैं। पांच साल में 22 तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के अलावा 188 पटवारी घूस लेते रंगेहाथ पकड़े गए हैं।

गौरतलब यह भी है कि प्रदेश के 1793 तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों में से हर पांचवा जांच के दायरे में है। रेवन्यू विभाग के 34 अफसर-कार्मिक तो ऐसे हैं, जिनके खिलाफ विभागाध्यक्षों ने अभियोजन स्वीकृति ही नहीं दी, जबकि ये रंगेहाथ पकड़े गए थे। इनमें से 20 मामलों में जांच अधिकारी सबूत तक दे चुके हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने माना है कि कैंपों में भी तहसीलदारों के खिलाफ शिकायतें आ रही है, इनमें कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं।

(दै.भा., 24.04.23, 06.05.23)

एसीबी दर्ज नहीं कर पा रही मामले

पिछले दो साल में प्रदेश में 556 लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को परिवाद मिले हैं। इनमें से सिर्फ 13 को मंजूरी मिली, 29 मामलों में मनाही और अब तक 514 मामले पेंडिंग है। इन 514 अधिकारियों के खिलाफ एसीबी पद के दुरुपयोग के मामले दर्ज नहीं कर पा रही। क्योंकि... पीसी एक्ट की धारा 17ए के तहत विभागाध्यक्ष मंजूरी नहीं दे रहे हैं।

उक्त मामलों में परिवादियों ने सबूतों सहित बताया है कि लोकसेवकों ने पद का दुरुपयोग किया है। एसीबी के अधिकारियों को भी लगा कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है और विस्तृत जांच जरूरी है। एसीबी ने इन मामलों को सरकार को भेजा। लेकिन इनमें से 514 परिवाद अब तक ऐसे हैं जिनमें भी संबंधित विभागाध्यक्ष जांच करने की अनुशंसा ही नहीं कर रहे।

(दै.भा., 31.05.23)

भारतीय अर्थव्यवस्था की रही उम्मीद से भी बेहतर रफ्तार

भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रतिकूल वैश्विक हालातों के बाद भी पिछले वित्त वर्ष में शानदार प्रदर्शन किया है। जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी की ग्रोथ रेट अनुमानों से बेहतर रही। मार्च तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 6.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि की, जबकि पूरे वित्त वर्ष-23 में आर्थिक वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही। इससे पहले दिसंबर तिमाही के दौरान 4.5 प्रतिशत रही थी। गौरतलब यह भी है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी जीडीपी ग्रोथ को लेकर कहा था कि हमें बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर भारत की जीडीपी 7 प्रतिशत से अधिक दर्ज की जाती है। *(रा.प.,01.06.23)*

मुफ्तदवा में राजस्थान पहले पायदान पर

सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में देश में राजस्थान पहले पायदान पर है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 76.02 फीसदी मरीजों को मुफ्त दवा मिल रही है। दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर तेलंगाना राज्य है।

यह खुलासा राज्यों के दवाओं की उपलब्धता की सॉफ्टवेयर के जरिए मॉनिटरिंग करने वाले केंद्र सरकार के ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम (डीवीडीएमएस) की अप्रैल 2023 की रिपोर्ट में हुआ है। अक्टूबर 2011 से संचालित निःशुल्क दवा योजना में बजट 195 करोड़ था, जो अब बढ़कर 1200 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत 14 करोड़ मरीज लाभान्वित हुए।

(दै.भा., 08.05.23)

श्री योजना में 402 विद्यालय चयनित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत शिक्षक दिवस पर पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना में पूरे देश में 14 हजार 597 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें राजस्थान के 402 विद्यालय शामिल है।

इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी। देश के स्कूलों को मॉडल स्कूलों का दर्जा देने के लिए 27 हजार 860 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। इसमें से 60 प्रतिशत राशि केंद्र तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक स्कूल में दो से ढाई करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इन स्कूलों को चयनित कर संस्था प्रधानों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। योजना के तहत 2027 तक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। *(रा.प., 12.04.23)*

भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश

दुनिया की आबादी अब 800 करोड़ के पार हो चुकी है। हर 5वें व्यक्ति में एक भारतीय है। क्योंकि भारत 142.86 करोड़ लोगों के साथ पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। चीन के 142.57 करोड़ के मुकाबले हमारी जनसंख्या 29 लाख ज्यादा है।

यूनाइटेड नेशंस पापुलेशन फंड (यूएनएफपीए) द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट-23 में यह आंकड़े सामने आए हैं। वर्ष 2022 में चीन की आबादी में 8.5 लाख की कमी आई है। वर्ष 1961 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। *(रा.प., 20.04.23)*

'हमें सुननी होगी धरती की पुकार'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संकटों से ग्रस्त विश्व में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा, आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से है। इन चुनौतियों का सामना करने में एक बाधा यह कि हम जलवायु परिवर्तन को ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। हमें चर्चा का दायरा बढ़ाना चाहिए।

मोदी ने यह बात जी-7 सम्मेलन के सातवें कार्य सत्र को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा जरूरतमंद देशों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण और किफायती ऋण उपलब्ध करा कर हम इन चुनौतियों से निजात पा सकते हैं। भारतीय सभ्यता में धरती को मां का दर्जा दिया गया है और सभी चुनौतियों के समाधान के लिए हमें पृथ्वी की पुकार सुननी होगी। उसके अनुरूप अपने आपको, अपने व्यवहार को बदलना होगा। इसी भावना से भारत ने पूरे विश्व के लिए मिशन लाइफ, अंतरराष्ट्रीय सौर गठजोड़, आपदा निरोधक अवसंरचना गठबंधन, मिशन हाइड्रोजन, जैव ईंधन गठजोड़, बिग कैट एलायंस जैसे संस्थागत समाधान खोजे हैं।

(रा.प., 21.05.23)

फूड सेफ्टी में सुधरी राजस्थान की रैंकिंग

केंद्र सरकार द्वारा जारी 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार खाने के मामले में केरल सबसे सुरक्षित राज्य है। देश के 20 बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा को लेकर केरल पहले स्थान पर है, जबकि पंजाब दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडू पहले से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

बीते साल केरल छठे व पंजाब 11वें स्थान पर था। राजस्थान भी 2 अंक के सुधार के साथ 10वें से 8वें पायदान पर आ गया। केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर तीसरे साल शीर्ष पर है, वहीं दिल्ली दूसरे और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, असम, बिहार व झारखंड का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। *(दै.भा., 09.06.23)*

—विकास के लिए—
तकनीक का लोकतंत्रीकरण जरूरी

वाराणसी में जी-20 सम्मेलन में दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े। उन्होंने 20 देशों से आए मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि हमें तकनीक का लोकतंत्रीकरण करना होगा, ताकि दुनिया से डेटा डिवाइड खत्म हो।

उन्होंने कहा महामारी के बाद दुनिया भर में भू-राजनैतिक तनाव की वजह से ग्लोबल साउथ देशों में खाना, खाद और ईंधन की कमी हो गई। हम सभी देशों की एक ही जरूरत है 'सतत् विकास'। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सदस्य राष्ट्र एक साथ विकास करें। कोई पिछड़ न जाए।

दै.भा., 13.06.23)

फ्री बिजली से बिगड़ा डिस्कॉम का गणित

राज्य सरकार की फ्री बिजली योजना ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का गणित बिगाड़ दिया है। डिस्कॉम को डर है कि भले ही सरकार ने फ्री बिजली के लिए 23 हजार करोड़ रखे हैं, लेकिन चुनावी साल के वक्त पर पैसा मिलना आसान नहीं है। हालात यह है कि इस योजना से कंपनियों का घाटा और बढ़ जाएगा।

अभी डिस्कॉम का करीब एक लाख करोड़ का घाटा है और सब्सिड़ी की भरपाई के लिए उनको प्रति वर्ष 60 हजार करोड़ रुपए लोन लेना पड़ता है। जिसका ब्याज सालाना लगभग 6500 करोड़ रुपए होता है। डिस्कॉम अभी सरकार से 14,800 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। उसका हिसाब भी बनाकर वित्त विभाग को भेजा है। लेकिन सरकार ने इस हिसाब में कमी बताते हुए 4,300 करोड़ रुपए इसमें से हटा दिए। इससे बिजली कंपनियों का घाटा और बढ़ गया। पैसा नहीं आने पर कंपनियों को बिजली खरीदने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, इसका भार आमजन के बिलों में जोड़ा जा रहा है।

(रा.प., 03.06.23)

बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत

चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब सभी उपभोक्ताओं को शुरुआती 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। वहीं, जिसकी विद्युत खपत 200 यूनिट प्रति माह है, उनका स्थाई शुल्क, फ्यूल सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी,अरबन सेस, जल संरक्षण उपकर भी माफ होंगे। उन्हें केवल सौ यूनिट का विद्युत शुल्क ही देना होगा।

इससे ज्यादा बिजली उपभोग करने वालों को अब कम बचत होगी। यानी, 200 यूनिट तक बिजली खपत करेंगे तो 980 रुपए की बचत होगी। इससे ज्यादा बिजली उपभोग करने वालों को अब 562 रुपए ही बचेंगे। अभी तक अधिकतम साढ़े सात सौ रुपए की सब्सिडी मिलती रही है। इसका अतिरिक्त भार राज्य सरकार वहन करेगी और बिजली कंपनियों को भुगतान किया जाएगा। घोषणा का लाभ लेने के लिए राहत शिविरों में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। *(रा.प. एवं दै.भा., 01.06.23)*

महंगे कोयले का बोझ जनता पर

महंगा कोयला खरीद के नाम पर डिस्कॉम ने लगातार तीसरे माह बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज का बोझ डाल दिया है। उपभोक्ताओं को जून के बिल में 52 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त राशि देनी होगी। इससे बिल में 150 से 1200 रुपए तक का भार आएगा। डिस्कॉम ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

इससे 1008 करोड़ रुपए की वसूली होगी। इसमें कृषि व 100 यूनिट तक फ्री बिजली उपभोक्ता भी शामिल हैं। इस सरचार्ज का भार सरकार उठाएगी, पर बोझ जनता पर ही आएगा। सौ यूनिट खपत वाले 1.04 करोड़ घरेलू और 15.70 लाख कृषि उपभोक्ता हैं। यह कोयला अपेक्षाकृत महंगा और कम गुणवत्ता का था।

(रा.प., 13.05.23)

दो लाख घरों तक नहीं पहुंची बिजली

केंद्र सरकार हर वंचित घर तक बिजली पहुंचाने पर जोर दे रही है और राज्य सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही है। लेकिन प्रदेश में 2 लाख परिवारों में बिजली ही नहीं है। बिजली कंपनियों ने सर्वे करवाकर इन्हें चिन्हित किया है।

प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों ने 1000 करोड़ रुपए की रिवेम्प डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) बनाकर ऊर्जा मंत्रालय को भेजी, वहां 6 माह से मामला पेंडिंग है। कई बार प्रजेंटेशन, केंद्र की टीमों की विजिट के बावजूद फंड नहीं मिला। फंड में देर होते देख मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले 2 लाख घरेलू कनेक्शन जारी करने के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की, लेकिन राज्य सरकार भी फंडिंग में ढिलाई बरत रही है। ऐसे में योजना शुरू ही नहीं हो पा रही।

(दै.भा., 28.04.23)

पवन ऊर्जाः राजस्थान पहले पायदान पर

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है।

'ग्लोबल विंड डे' के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मंत्रालय के सचिव बी.एस.भल्ला ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए. सावंत को पुरस्कार सौंपा। इस पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बधाई दी। कार्यक्रम में सावंत ने बताया कि वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 867 मेगावाट क्षमता की नई पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है। वर्ष 2022 में 4337 मेगावाट स्थापित की गई थी।

(रा.प., 16.06.23)

डिस्कॉम ने किराए पर सौंपे पोल

जयपुर शहर में बिजली के आधे पोल को किराए पर सौंप दिया गया है। करीब एक लाख 35 हजार पोल पर तारों का जाल बिछा है और इन पर लटके भारी बॉक्स हादसों को न्योता दे रहे हैं। इससे हजारों लोग सहमे हुए हैं, खासकर ऐसे लोग जिनके घरों के बाहर ही बिजली का पोल लगा है।

कमाई के लालच में डिस्कॉम मोबाइल व ब्रॉडबैंड कंपनी, केबल ऑपरेटर्स के साथ लगातार अनुबंध कर रहा है। सरकार ने भी कुछ माह पहले इनका मासिक किराया 1500 रुपए से घटाकर 1000 रुपए प्रति पोल कर दिया। जबकि मुहिम तारों को भूमिगत करने की चलती रही है। कुछ कंपनियों और अफसरों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। मसलन, इन कंपनियों ने ओवरहैड केबल के लिए अनुमति तो एक पोल की ली, लेकिन तार पांच पोल पर खेंच दिए। हैरानी की बात है कि इसकी जानकारी अफसरों को है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। *(रा.प., 21.04.23)*

हो सकेगी 24 घंटे पानी की सप्लाई

अभी जयपुर शहर में पेयजल वितरण तंत्र काफी पुराना है। पानी के प्रेशर से ही कई सालों पुरानी पानी की लाइनें टूट जाती है। अब अमृत-2 के तहत पूरे शहर की जर्जर हो चुकी पानी की लाइनों को बदला जाएगा। परकोटे की तर्ज पर छोटे-छोटे डीएमए बनाए जाएंगे और इनमें पानी सप्लाई के लिए अलग से फीडर होगा। जिससे पूरे 24 घंटे जरूरत के अनुसार पानी की सप्लाई आसानी से की जा सकेगी।

इसके साथ ही पंप हाउस भी सौर ऊर्जा से चलाए जाएंगे। अभी जयपुर शहर में पेयजल व्यवस्था के लिए 200 से ज्यादा पंप हाउस हैं। इन पंप हाउस का बिजली का बिल हर महीने करोड़ों रुपए का होता है। इन पंप हाउस पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे बिजली बिल का मोटा खर्चा कम हो सकेगा। बीसलपुर बांध को चंबल के पानी से भरा जाएगा। इससे जयपुर शहर को मिलने वाले अतिरिक्त पानी से शहर की लाखों की आबादी को पेयजल मिलेगा।

(रा.प., 13.04.23)

घरों में लगेंगे पानी के स्मार्ट मीटर

जलदाय विभाग की जयपुर शहर में 15 हजार स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी चल रही है। इस पर 12.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खास बात यह है कि दो वर्ष पहले जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने में जिन इंजीनियरों की नाकामी सामने आई, उनको ही यह जिम्मा फिर से सौंपा गया है।

मुख्य अभियंता (शहरी) केडी गुप्ता ने जयपुर में 15 हजार जोधपुर में 10 हजार और कोटा में 5 हजार स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश जारी किए है। इस कार्य के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता आर.सी. मीणा को नोड़ल अधिकारी बनाया गया है। माना जा रह है कि स्मार्ट मीटर से पानी की बूंद-बूंद का हिसाब रखना जहां आसान होगा, वहीं पानी की चोरी का पता भी आसानी से लग सकेगा। *(रा.प., 05.06.23)*

पेयजल परियोजनाओं को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 23 हजार 941 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इससे 11 जिलों के 5 हजार 739 गांवों में 15.50 लाख जल कनेक्शन होंगे। जल जीवन मिशन की राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति की 37वीं बैठक में यह मंजूरी दी गई।

इसके अलावा 130 करोड़ 38 लाख रुपए की 33 गांवों की 59 नई लघु पेयजल परियोजनाओं (ओटीएमपी) को स्वीकृति मिली। इन परियोजनाओं में 13 हजार 132 जल कनेक्शन होंगे। जोधपुर व अन्य जिलों के लिए 400 करोड़ रुपए से ज्यादा पेयजल योजनाओं के साथ ही जयपुर जिले के लिए 291 करोड़ रुपए की 147 पेयजल परियोजनाओं को भी मंजूरी मिल गई है। *(रा.प. एवं दै.भा., 31.05.23)*

मुफ्त पानी की घोषणा पर फेरा पानी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2019 में पेयजल उपभोक्ताओं को 15 हजार लीटर तक पानी मुफ्त देने की घोषणा की थी। लेकिन जलदाय विभाग के इंजीनियर चार साल से शहर के डेढ़ लाख से ज्यादा खराब मीटर को नहीं बदल सके। इसका नतीजा यह हुआ कि पेयजल उपभोक्ता आज भी इस छूट से वंचित हैं और उनसे औसत बिल के आधार पर जलदाय विभाग 300 से 800 रुपए तक वसूल रहा है।

जलदाय विभाग के कार्यालयों में हजारों उपभोक्ता अपने बिल लेकर 15 हजार लीटर की छूट लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इंजीनियर बिल देख कर कहते है कि मीटर खराब होने के कारण यह छूट नहीं मिल सकती। उपभोक्ता दावा करते हैं कि घर में 15 हजार लीटर पानी का उपयोग है ही नहीं। लेकिन जलदाय विभाग के अफसर उनकी नहीं सुनते। आज तक विभाग द्वारा नए मीटर खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया ही शुरू नहीं की गई। *(रा.प., 11.06.23)*

जयपुर शहर में अमृत-2 की तैयारी शुरू

जयपुर शहर में परकोटा के जलापूर्ति तंत्र को सुधारने के लिए 50 करोड़ की लागत वाला अमृत-1 प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। अब जलदाय विभाग पूरे शहर में अमृत-2 शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 1300 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो गया है। प्रोजेक्ट अगर बेहतर तरीके से पूरे शहर में लागू होता है तो इससे आमजन को फायदा होगा।

साथ ही विभाग की ओर से शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग के अधीन रुडसिको (राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन) को भेज दिए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 3 महीने बाद शहर में अमृत-2 का काम धरातल पर दिखने लगेगा। नई लाइन बिछने से दूषित पानी की समस्या खत्म होगी और कम प्रेशर से पानी आने की समस्या से भी निजात मिल सकेगी। *(रा.प., 18.06.23)*

भूजल दोहन से नीचे पहुंचा भूजल स्तर

बेतरतीब तरीके से भूजल दोहन के चलते जयपुर में पिछले डेढ़ साल में ही भूजल स्तर दो मीटर तक नीचे चला गया। यहां 16 में से 15 ब्लॉक अति दोहित हैं और एक ब्लाक क्रिटिकल स्थिति में है। इसके बावजूद शहर में ही करीब दो हजार अवैध ट्यूबवैल से पानी खींचकर चांदी कूटी जा रही है।

जिला प्रशासन और भूजल विभाग अवैध तरीके से पानी का कारोबार करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पानी टैंकर संचालन, आरओ प्लांट, होटल रिसोर्ट से लेकर कई औद्योगिक भवन परिसर में हर दिन करीब 13 करोड़ लीटर पानी का उपयोग हो रहा है। यह पानी अवैध तरीके से जमीन से खेंचा जा रहा है। इसमें से 2 से 3 करोड़ लीटर पानी अकेले निजी टैंकरों से बेचा जा रहा है। इस अंधाधुंध दोहन से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। भूजल विशेषज्ञों के अनुसार जयपुर में भूजल भंडार समाप्ति की ओर है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की हाल ही रिपोर्ट में सभी 16 ब्लॉक अति दोहित श्रेणी में आए हैं।

(रा.प., 07.05.23)

मिशन डिजिटल महिला का शुभारंभ

जी-20 देशों की महिलाओं की जयपुर में हुई दो दिवसीय डब्ल्यू-20 समिट में 'महिलाओं का नेतृत्व, समावेशी और सशक्त भविष्य' थीम पर आधारित दो दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन जी-20 शेरपा अमिताभ कांत, नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उपस्थिति में मिशन डिजिटल महिला का शुभारंभ किया गया।

उद्घाटन सत्र में डब्ल्यू-20 की अध्यक्ष संध्या पुरेचा ने कहा कि आगामी वर्षों में दस लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य है। डब्ल्यू-20 इंडिया की मुख्य समन्वयक धारित्री पटनायक ने कहा कि दुनियाभर में महिलाओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए 'कॉल टू एक्शन' पहल शुरू की जाएगी। सम्मेलन में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, लैंगिक डिजिटल असमानता जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार रखे। केंद्रीय संस्कृति राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूह देश में महिला सशक्तीकरण की मिसाल है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए जारी योजनाओं और किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। *(रा.प., 14.04.23)*

नहीं पहुंच रहे डिजिटल परिवर्तन के लाभ

देश-दुनिया के अध्ययन बताते हैं कि भारत समेत उच्च, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डिजिटल परिवर्तन के लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंच रहे हैं। इससे हर साल विश्व की करीब एक खरब डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। महिलाएं मोबाइल और इंटरनेट से दूर रही तो 2025 तक यह नुकसान 1.5 खरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।

यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 90 फीसदी नौकरियों में डिजिटल कारक प्रमुख है। हालांकि यह नौकरियां महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा मिली हैं। वजह साफ है कि विकासशील देशों में 53 फीसदी पुरुषों की तुलना में 41 फीसदी महिलाओं की ही इंटरनेट तक पहुंच है। *(रा.प., 22.05.23)*

दूध उत्पादन में पहले नंबर पर राजस्थान

केंद्र सरकार के पशुपालन व मत्स्य विभाग द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी-2022 के नवीनतम आंकड़ों में राजस्थान देश में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है।

प्रदेश में देश का 15.05 प्रतिशत दूध उत्पादन हो रहा है। उत्तर प्रदेश 14.93 प्रतिशत के साथ दूसरे व मध्यप्रदेश 8.06 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। दूध उत्पादन की इस तस्वीर को बदलने में व्यावसायिकता के साथ घरेलू डेयरियों में जुटी महिलाओं का बड़ा योगदान है। प्रदेश में पिछले वर्ष लम्पी बीमारी की वजह से दूध उत्पादन लड़खड़ाया, लेकिन अब फिर से नवाचार के बल पर प्रदेश की 'आधी आबादी' ने यह करिश्मा कर दिखाया। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से 280 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता अनुमोदित की गई है। जबकि प्रदेश में 870 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध है।

(रा.प., 01.06.23)

व्यवसाय में भी बढ़ रही 'महिला शक्ति'

देश की महिलाएं खुद का बिजनेस शुरू करने के मामले में भी कहीं आगे है। इस मामले में हम दुनिया की टॉप-5 इकोनॉमी वाले देशों में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर हैं। आबादी में हमसे लगभग बराबरी पर खड़े चीन से तुलना करें तो पिछले साढ़े 3 साल में अपना बिजनेस शुरू करने वाली महिलाओं की संख्या चीन के मुकाबले भारत में दोगुने से भी ज्यादा है।

देश में नए उद्यमियों में महिलाओं की हिस्सेदारी जहां 11 प्रतिशत तक है, वहीं चीन में यह आंकड़ा सिर्फ 5 प्रतिशत पर अटका है। अमेरिका में यह हिस्सेदारी 18 प्रतिशत, जर्मनी में 7 प्रतिशत और जापान में सिर्फ 3.6 प्रतिशत है। ग्लोबल आंत्रप्रिन्योरशिप मॉनीटर की 2022-23 की ग्लोबल रिपोर्ट में यह तस्वीर सामने आई है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए बेहतर देशों में भी यूएई, सऊदी अरब, ताइवान के बाद भारत चौथे स्थान पर है। *(दै.भा., 09.05.23)*

महिलाएं दे रही घर खर्च में मदद

कामकाजी महिलाएं घर की जिम्मेदारियां तो कंधों पर लेकर चलती ही हैं, अब वे घर खर्च में भी मदद कर रही हैं। देश में करीब 70 फीसदी कामकाजी महिलाएं घर खर्च में सक्रिय रूप से योगदान देती हैं। वर्किंगस्त्री शीर्षक से जारी रिपोर्ट से यह खुलासा सामने आया है।

रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय आजादी और इससे जुड़े फैसले लेने को लेकर महिलाओं का नजरिया अनूठा है। दिल्ली की करीब 32 फीसदी महिलाओं ने कहा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले लेने में वे थोड़ी कठिनाई महसूस करती है। यह बात देशव्यापी स्तर पर एक जैसी है। महिलाएं वित्तीय फैसले लेने में पिता, भाई व पति की सलाह पर निर्भर करती हैं। इंडियालेंड्स के सीईओ गौरव चौपड़ा कहते हैं महिलाओं के वित्तीय अधिकार सामाजिक जिम्मेदारी तो है ही, आर्थिक विकास में भी सहायक है।

(दै.भा., 27.04.23)

उच्च शिक्षा में महिलाओं के बढ़ते कदम

विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। विदेशी शिक्षा सलाहकारों और ऋण प्रदाताओं का कहना है कि ऋण की आसान उपलब्धता, स्कॉलरशिप और अन्य प्रोत्साहनों जैसे कारकों ने आधी आबादी के कदमों को रफ्तार दी है।

वर्ष 2019 के मुकाबले पिछले साल महिला आवेदकों की संख्या में 100 से 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति आने वाले साल में भी जारी रहेगी। अमरीका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में जाकर महिलाएं अपनी पढ़ाई के सपनों को पूरा कर रही हैं। मैनेजमेंट,अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग सहित एनालिटिक्स और पब्लिक हेल्थ जैसे कोर्सेज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

(रा.प., 31.05.23)

बीमारी से ज्यादा सड़क हादसों में मौत

प्रदेश में हर साल 10 हजार लोग सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं और यह आंकड़ा कई बड़ी बीमारियों से भी बहुत अधिक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से आज तक 9,730 लोगों की मौत हुई है, जबकि हार्ट अटैक से हर साल 1200-1300 लोगों की जान जा रही है। लेकिन सड़क हादसों में हर साल पूरे प्रदेश में 10 हजार लोगों की मौत होना चिंताजनक है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है।

पिछले पांच वर्षों में राजस्थान सड़क हादसों के मामले में देश में नवें स्थान पर रहा है, वहीं नेशनल हाईवे पर हादसों में हुई मौतों में देश में चौथे स्थान पर है। पिछले एक साल में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं 23 फीसदी से अधिक हुई हैं। पिछले पांच वर्ष में किसी भी साल में दुर्घटनाओं में इतनी बढ़ोतरी एक साथ नहीं हुई।

(रा.प., 22.05.23)

ब्लैक स्पॉट कर रहे सड़कों को लाल

प्रदेश की सड़कों पर 600 ऐसे स्थान हैं, जहां दुर्घटनाओं का खतरा ज्यादा है। ब्लैक स्पॉट्स से बेखबर बाहरी वाहन चालक यहां ज्यादा शिकार हो रहे हैं। प्रदेश में औसतन हर दूसरी दुर्घटना में मौत हो रही है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर एक तिहाई दुर्घटनाओं में ही मौत हो रही है।

प्रदेश के सड़क सुरक्षा वॉर रूम के अध्ययन से यह खुलासा हुआ है। पुलिस के आंकड़ों से सामने आया है कि इस साल जनवरी से अप्रैल तक प्रदेश में 2047 सड़क दुर्घटनाओं में 1028 लोगों की मौत हुई। जयपुर ग्रामीण पुलिस क्षेत्र, भीलवाड़ा, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर व उदयपुर जिले में दुर्घटना में मौतें ज्यादा होती है। प्रदेशभर में हुई मौतों में से 10 प्रतिशत अकेले जयपुर जिले में होती है और इसमें भी जयपुर ग्रामीण क्षेत्र आगे है। *(रा.प., 19.05.23)*

नाम के बना दिए ट्रोमा सेंटर

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ को देखते हुए विभिन्न जिलों में 57 ट्रोमा सेंटर हैं। इनमें जयपुर जिले के दूदू, कोटपूतली, चौमूं और शाहपुरा शामिल है। इनमें से अधिकांश केंद्र सिर्फ नाम के हैं और सिर्फ जिला व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की इमरजेंसी में रहने वाली सुविधाओं के भरोसे है। इन अस्पतालों में जाने पर उन्हें रेफर कर दिया जाता है।

इससे घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए जरूरी गोल्डन ऑवर्स खराब हो जाते हैं। ट्रोमा सेंटर की गाइडलाइन के अनुसार गंभीर घायल को तत्काल समुचित उपचार देने के लिए न्यूनतम एक-एक हड्डी, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, न्यूरोसर्जरी व ऐनेस्थीसिया का विशेषज्ञ ट्रोमा सेंटर में होना ही चाहिए, लेकिन अधिकांश में सभी डॉक्टर नहीं है। जबकि अक्सर इमरजेंसी के केस में घायल को रेफर करना ही पड़ता है।

(रा.प., 29.05.23)

प्रदेश में रफ्तार ने छीनी जिंदगियां

राजस्थान में हर साल रोड सेफ्टी के नाम पर 70 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। इसके बावजूद न हादसे रुक रहे हैं न हादसों में मौतें। देश में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं के मामले में तो राजस्थान 9वें स्थान पर है, लेकिन हादसे में होने वाली मौतों के मामले में चौथे स्थान पर है।

राज्य राजस्व अधिसूचना निदेशालय ने वर्ष 2021 में हुए सड़क हादसों पर विस्तृत समीक्षा की है। इसकी 15 मई 2023 को जारी रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इसके अनुसार, वर्ष 2021 में प्रदेश में 20,951 एक्सीडेंट हुए हैं। इनमें 19,344 घायल और 10,043 लोगों की मौत हुई है।

सबसे अधिक हादसे ओवरस्पीडिंग के चलते हुए। ओवरस्पीडिंग से वर्ष 2021 में 17,094 एक्सीडेंट हुए, जिसमें 8,236 लोगों की मौत हो गई। हादसों की अन्य वजह में ओवरलोडिंग, ओवरटेक, ड्रिंक एण्ड ड्राइव, रैश ड्राइविंग आदि है। हादसे के शिकार सबसे ज्यादा 25 से 35 आयु वर्ग के युवा हो रहे हैं। *(दै.भा., 13.06.23)*

प्रदेश के 27 भले लोग हुए पुरस्कृत

राजस्थान में 15 जिलों के 27 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने सड़क हादसों में घायल की मदद कर उनको समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनका जीवन बचाया है। राज्य सरकार ने इन लोगों को भले लोग (गुड सेमेरिटन) नाम दिया है। सभी 27 भले व्यक्तियों को राज्य सरकार की ओर से जीवन रक्षक योजना में प्रोत्साहन राशि के तहत 5 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। इन 27 भले लोगों में सबसे अधिक 11 व्यक्ति शेखावाटी क्षेत्र के हैं।

सड़क दुर्घटना के बाद वहां मौजूद लोग दुर्घटना में घायलों को कानूनी कार्रवाई के डर से अस्पताल ले जाने से बचते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना शुरू की। इसमें दुर्घटना में घायल को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है।

(दै.भा., 08.05.23)

घर बैठे आएंगे चालान, होगी मॉनिटरिंग

बढ़ते सड़क हादसों में कमी लाने के लिए अब हाईवेज पर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) का प्रयोग किया जाएगा। इस सिस्टम के माध्यम से ओवर स्पीड, लाइन सिस्टम की पालना नहीं करने वाले और गलत साइड चलाने वाले वाहन मालिकों पर नकेल कसी जाएगी।

नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन मालिकों के घर बैठे चालान आएंगे। शुरुआत में प्रदेश के तीन नेशनल हाईवेज पर आईटीएमएस लागू किया जा रहा है। इसमें शाहजहांपुर से अजमेर, सीकर से बीकानेर और जोधपुर नेशनल हाईवेज शामिल है। 100 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट को राज-कॉम इंफॉर्मेटिव सर्विस लिमिटेड के माध्यम से अमलीजामा पहनाया जाएगा। तीनों हाईवेज पर कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें सेंसर लगे होंगे। यह कैमरे परिवहन विभाग के ई चालान पोर्टल से लिंक होंगे। *(दै.भा., 21.04.23)*

उपभोक्ता फैसले

महंगा पड़ा डाकघर को पीपीएफ पर ब्याज रोकना

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-3 में कुलदीप कुमार गुप्ता ने शास्त्रीनगर स्थित पोस्ट ऑफिस (डाक विभाग) के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। उन्होंने परिवाद में बताया कि अगस्त, 2004 में उसने और उसके पिता ने एचयूएफ (हिंदू अविभाज्य परिवार) की हैसियत से शास्त्री नगर पोस्ट ऑफिस में दो पीपीएफ खाते खुलाए थे। पोस्ट ऑफिस ने पीपीएफ खाते की 15 साल की अवधि पूरी होने पर उसके पिता के खाते का भुगतान कर दिया। लेकिन पोस्ट ऑफिस ने मेरे (परिवादी) खाते में दिया ब्याज रिकवर करने के आदेश दे दिए। जबकि उन्होंने एचयूएफ के सदस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं छुपाई है। कानूनन रूप से बेटा, छोटी एचयूएफ का सृजन कर सकता है। ऐसे में उसे ब्याज सहित राशि दिलाई जाए।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने खाताधारक को दो एचयूएफ (हिंदू अविभाज्य परिवार) का सदस्य बताकर उसके पीपीएफ खाते का ब्याज रोकने को सेवा दोष माना। आयोग ने डाक विभाग पर 1.25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही पीपीएफ खाते की ब्याज राशि 31 मार्च, 2020 से नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। *(दै.भा., 04.05.23)*

गर्भवती की मौत, अस्पताल पर लगाया जुर्माना

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने चिकित्सीय लापरवाही के मामले पर बेंगलुरू के संतोष अस्पताल प्रबंधन पर डेढ़ करोड़ रुपए और एनेस्थेटिस्ट पर दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने फैसले में कहा है कि अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर जुर्माना राशि को शिकायतकर्ता पति और मृतका के माता-पिता को मुआवजे के तौर पर 7 फीसदी ब्याज सहित 6 सप्ताह के भीतर अदा करेंगे। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन शिकायतकर्ताओं को केस खर्च के रूप में 2 लाख रुपए अलग से देगा। आयोग ने अस्पताल प्रबंधन की सभी दलीलों को खारिज कर दिया।

यह मामला बेंगलुरू की एक गर्भवती महिला कपाली पाटने की और उसके अजन्मे बच्चे की डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान बरती गई चिकित्सीय लापरवाही से हुई मौत से संबंधित है। महिला के पति परिक्षित दलाल, उसके ससुर सुरेश जे पाटने और सास मीना एस पाटने ने अस्पताल के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग में शिकायत दायर की थी। आयोग ने एक अलग व अजीब तरह की शर्त भी शिकायतकर्ता पति के लिए निर्धारित की है। आयोग ने फैसले में कहा कि अगर मृतका का पति दोबारा शादी करता है तो मुआवजे की सारी राशि उसके सास-ससुर यानी पत्नी के मां-बाप को दी जाएगी। *(दै.भा., 01.06.23)*

टीवी-एसी, फ्रिज की रिपेयरिंग से पल्ला नहीं झाड़ पाएंगी कंपनियां

ज्यादातर कंपनियां अपने उत्पाद बेचते समय लंबे-चौड़े वादे करती हैं। वो गारंटी और वारंटी के साथ सामान तो बेच देती हैं, लेकिन बाद में खराबी आने पर मरम्मत को लेकर आनाकानी करती हैं। खासकर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद समय से पहले खराब होने पर उपभोक्ताओं को लंबी दौड़ लगानी पड़ती है। लेकिन कई मामलों में कंपनियां किसी न किसी बहाने बिना शुल्क मरम्मत करने से बचती हैं, या फिर रिपेयरिंग के लिए अलग से फीस या सर्विस चार्ज भी देने के लिए कहा जाता है।

केंद्र सरकार ने अब उपभोक्ताओं को नया अधिकार दिया है। जिसके तहत मोबाइल, टैबलेट जैसे गैजेट, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, भारी कृषि मशीनरी की लाइफ तय होगी। कंपनी को उपभोक्ता को उसके रखरखाव और रिपेयर की पूरी जानकारी देनी होगी। खराब होने पर संबंधित पुर्जा ही बदलने की जरूरत होगी, लेकिन कोई नया सामान बेचने की आड़ में कंपनियां ग्राहकों को झांसा नहीं दे पाएंगी।

राष्ट्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के विभाग ने इसके लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल भी शुरू किया है। खबरों के मुताबिक उपभोक्ताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए और तमाम झंझटों से मुक्ति के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल में दी गई जानकारी के अनुसार उपभोक्ताओं की मदद के लिए इसमें एलजी, ओप्पो केयर, बोट, हैवेल्स, एचपी, केंट, सैमसंग और होंडा मोटर्स जैसे ब्रांड को जोड़ा गया है। इस पोर्टल पर उत्पादों से जुड़ी मरम्मत व अन्य शिकायतों के लिए मदद मिल पाएगी।

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिगटन डी.सी. (यूएसए)